

- देहरादून
- वर्ष 33
- अंक 330
- पृष्ठ 8
- मूल्य ₹ 1.00



दून वैली मेल

सांध्य दैनिक

आर.एन.आई. : 59626/94

email: doonvalley_news@yahoo.com

Website: dunvalleymail.com

डीएवीपी से मान्यता प्राप्त

एयरपोर्ट रूट पर लूट करने वाले गिरफ्तार

‘दून वैली मेल’ के द्वारा मामला उठाने पर पुलिस आई हरकत में



संवाददाता

देहरादून। सांध्य दैनिक ‘दून वैली मेल’ के द्वारा मामला उठाये जाने के बाद एयरपोर्ट रूट पर लूट करने वाले चार लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट में प्रयुक्त बेसबॉल के डंडे, खुखरी व नकली पिस्टल व कार बरामद कर ली है।

सांध्य दैनिक ‘दून वैली मेल’ द्वारा गत एक जनवरी को समाचार ‘भजन गायक पर जानलेवा हमला कर लूट का

प्रयास, प्रकाशित किया था। दून वैली मेल के खुलासे के बाद पुलिस-प्रशासन हरकत में आया और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। घटना के अनुसार भजन गायक दीपक कुमार टिहरी से 31 दिसम्बर की रात्रि टीएचडीसी से प्रोग्राम खत्म कर अपने घर वापस आ रहे थे जब वह रात्रि तीन बजे थानों के जंगल में पहुंचे तभी कार सवार बदमाशों ने उनकी कार पर डण्डों से हमला कर उनकी कार को क्षतिग्रस्त कर दिया था। जिसके बाद

दीपक कुमार ने किसी तरह से कार की स्पीड तेज कर वहां से भागकर अपनी जान बचायी। जिसके बाद उन्होंने रायपुर पहुंचकर घटना की पुलिस को जानकारी दी। घटना का पता चलने पर एसएसपी अजय सिंह के निदेश पर टीमों का गठन किया गया। वहीं लक्कडघाट निवासी मंजीत सिंह राठौर ने भी डोईवाला कोतवाली में थानों मार्ग पर उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया। जिसके बाद पुलिस ने क्षेत्र

में सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया तथा मैनुअल जांच करते हुए गत दिवस रात्रि में चैकिंग के दौरान रायपुर स्टेडियम मार्ग से घटनाओं में शामिल चार लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं इनके साथ तीन अन्य विधि विवादित किशोरों को भी पुलिस संरक्षण में लिया गया। पुलिस ने उनके कब्जे से एक स्वीफ्ट कार, बेसबॉल के डण्डे, नकली पिस्टल, खुखरी व रिफ्लेक्टर पिलर बरामद कर लिये। पूछताछ में उन्होंने अपने नाम पारस पुत्र दीपक

कुमार निवासी नंद कालोनी नत्थुवाला, साहिल राणा पुत्र इन्द्रजीत सिंह राणा निवासी पदम निवास घोडा फैक्ट्री रोड बालावाला, प्रियांशु राणा पुत्र अब्बल सिंह राणा निवासी सोडा सरोली रायपुर, अमन उर्फ एमी पुत्र देवेन्द्र सिंह बुटोला निवासी कृष्ण विहार गुजरोवाली बताया। पुलिस ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको न्यायालय में पेश किया जहां से उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

दून वैली मेल

संपादकीय

आक्रोश में देश की राजनीति

जी हां यही आपका नया भारत, बदलता भारत और महान भारत है जिसका ढिंढोरा भाजपा का शीर्ष नेतृत्व 2014 के चुनाव के बाद से लगातार पीटता चला आ रहा है। भाजपा नेताओं ने देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं में फेर बदल के जरिए बीते 10 सालों में सत्ता का रुख अपनी ओर मोड़ लिया है। सत्ता की अतिवादी नीतियों ने संविधान व लोकतंत्र तथा उन सभी संवैधानिक स्थानों को हैक कर लिये जाने से सत्ता लगातार अपनी मनमानियों के दम पर आगे बढ़ता दिख रहा है। और उसे ऐसा करने से कोई रोक भी नहीं पा रहा है जो न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि चिंताजनक ही है। गोधरा अग्निकांड के बाद गुजरात में घटित होने वाली तथा महिलाओं के सम्मान को तार-तार करने वाली घटनाओं को भारत देश के लोग कैसे भूल सकते हैं जब बिलकिस बानो के दोषियों को जेल से रिहा कर दिया जाता है तथा इस रिहाई का जश्न उन्हें फूल मलायें पहना कर किया जाता है इससे बड़ी शर्मसार करने वाली कोई दूसरी घटना भला क्या हो सकती है। अभी बीते दिनों उत्तराखंड में यूकेएसएसएससी मामले में सरकार ने हर संभव तथ्य को नकारने की कोशिश की गई कि यह पेपर लीक घटना नहीं है और जब आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया तो सरकार द्वारा इसकी सीबीआई जांच की संस्तुति की गई। अकिता भंडारी मर्डर केस की फाइल चीख-चीख कर पहले ही दिन से यह कह रही है कि उसमें अन्य उनसे अधिक लोगों की संलिप्तता थी। जबकि सरकार उन्हें बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाए हुए हैं लेकिन यह मानने को तैयार नहीं है कि हां अगर कोई वीआईपी इसमें संलिप्त है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अब तक इसकी निष्पक्ष जांच को लेकर तीन नेताओं के इस्तीफे भी हुए हैं फिर भी सरकार हठ धर्मिता छोड़ने को तैयार नहीं है बिना इसकी सीबीआई जांच करा कर अब इसका समाधान संभव नहीं है। लेकिन एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन चुके इस केस में सरकार अपनी पूरी छीछालेदर करने को तैयार नहीं है। आज हमारे दिमाग में एक और बात आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार द्वारा क्या मोदी सरकार को इसलिए समर्थन दिया गया था कि वह अपनी मनमानी करते रहें। भले ही 2014 और 2019 में भाजपा को अपने दम पर दो बार सरकार बनाने का मौका मिला हो लेकिन 2024 में तो जनता ने उसे सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। आज देश के युवाओं और आधी आबादी में अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए जो सवाल खड़े हो रहे हैं वह चंद्रबाबू नायडू व नीतीश के कारण ही दिखाई दे रहे हैं। नीतीश बाबू को तो न तो चुनाव आचार संहिता के दौरान उनके राज्य की महिलाओं को 10-10 हजार कैश देकर उनके वोट खरीदने का काम किया गया उसमें उन्हें कोई भी बुराई दिखी होगी न ही उत्तराखंड की महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के पति द्वारा इस बयान पर कोई शर्मिंदगी महसूस हुई होगी जिसमें उन्होंने कहा है कि बिहार में 20-30 हजार में लड़कियां मिलती है चाहे जितनी खरीद लो। धन्य है इस देश के नेता जिन्हें किसी बात पर कोई शर्मिंदगी ही नहीं। ऐसे नेताओं को देश का युवा कब सबक सिखाएगा यह आने वाला समय ही बताएगा।

यूपीसीएल द्वारा दिव्यांगजनों को पदोन्नति में 4 प्रति. आरक्षण न देना दिव्यांग अधिकार अधिनियम का उल्लंघन: डोभाल

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड के सदस्य अमित डोभाल ने उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को पदोन्नति में दिए जाने वाले 4 प्रतिशत आरक्षण को लगातार अनदेखा किया जा रहा है, जो कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 का स्पष्ट उल्लंघन है।

अमित डोभाल ने कहा कि राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड के सदस्य होने के नाते उनका कर्तव्य है कि वे दिव्यांगजनों के हक और अधिकारों की रक्षा करें तथा उन्हें उनका वैधानिक अधिकार दिलाने के लिए आवाज उठाएं। हाल ही में उनके संज्ञान में आया है कि उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में कार्यरत अनेक दिव्यांग कर्मचारी पदोन्नति के लिए पात्र होने के बावजूद वर्षों से अपने अधिकार से वंचित हैं। उन्होंने बताया कि सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार विभाग में दिव्यांगजनों को पदोन्नति में 4% आरक्षण देने में गंभीर लापरवाही बरती जा रही है, जबकि पूर्व में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में दिव्यांग अधिकार अधिनियम के तहत आरक्षण का लाभ दिया जा चुका है तथा इस संबंध में विभागों को कई बार स्पष्ट निर्देश भी जारी किए गए हैं। अमित डोभाल ने कहा कि नब्बे में कई दिव्यांग कर्मचारियों ने आरक्षण नियमों के तहत अपनी आवश्यक सेवा अवधि भी पूर्ण कर ली है, इसके बावजूद आज तक किसी भी दिव्यांगजन को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और अन्यायपूर्ण है।

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा शीघ्र ही पदोन्नति में दिव्यांगजन आरक्षण का संज्ञान नहीं लिया गया और दिव्यांग कर्मचारियों को उनका वैधानिक अधिकार नहीं दिया गया, तो इसका घोर विरोध किया जाएगा और यह मामला शासन एवं सक्षम मंचों पर मजबूती से उठाया जाएगा।

5 जनवरी को कालसी में आयोजित होगा वृहद बहुउद्देशीय शिविर

संवाददाता

देहरादून। जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान के अंतर्गत प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में 05 जनवरी, 2026 को प्रातः 11 बजे से अपराह्न 4 बजे तक विकासखंड कालसी स्थित पंजीटिलानी मिनी स्टेडियम में वृहद बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जाएगा।

जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान के अंतर्गत प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में 05 जनवरी, 2026 को प्रातः 11 बजे से अपराह्न 4 बजे तक विकासखंड कालसी स्थित पंजीटिलानी मिनी स्टेडियम में वृहद बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप यह शिविर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने एवं जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए जाएंगे, जिनके माध्यम से सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुँचाने का लक्ष्य निश्चित किया गया है। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे शिविर में पूर्ण तैयारी के साथ प्रतिभाग करें तथा पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करें। सभी विभाग आवेदन प्रपत्रों एवं योजनाओं से संबंधित संपूर्ण जानकारी के साथ शिविर स्थल पर उपस्थित रहेंगे।

मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने बताया कि बहुउद्देशीय शिविर में जनपद स्तरीय अधिकारी स्वयं उपस्थित रहकर जन समस्याओं का मौके पर



निस्तारण करेंगे तथा विभागीय स्टॉलों के माध्यम से योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। बहुउद्देशीय शिविर में समाज कल्याण, महिला कल्याण एवं प्रोबेशन विभाग द्वारा वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, किसान व परित्यक्ता पेंशन प्रकरणों सत्यापन के साथ छात्रवृत्ति,

शिविर में ही जारी होंगे आयुष्मान, दिव्यांग व अन्य प्रमाण पत्र

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, शादी अनुदान फार्म भरवाए जाएंगे। डीडीआरसी के माध्यम से दिव्यांगों के यूडीआईडी कार्ड, कुपोषित बच्चों का चिन्हीकरण, उपचार, दिव्यांग एवं कृत्रिम अंगों का वितरण किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविर में दो स्तरीय व्यवस्था रहेगी। पहला सामान्य जांच शिविर का आयोजन और दूसरा विभिन्न प्रकार के दिव्यांग प्रमाण पत्र ऑफलाइन बनाने के उपरांत बाद में ऑनलाइन करने हेतु एसडीएम को दिए जाएंगे। आरबीएस की टीम कुपोषित बच्चों का सर्वे कर उपचार प्रदान करेगा। शिविर में नशा मुक्ति

काउंसलिंग, पोषण, परिवार कल्याण, टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क जांच व औषधि वितरण किया जाएगा। अटल आयुष्मान कार्ड के लिए पृथक सीएचसी संचालित कर कैंप में ही आवेदकों को कार्ड निर्गत किए जाएंगे। शिविर में नेत्र परीक्षण व चश्मों भी वितरित किए जाएंगे। आईसीडीएस विभाग द्वारा कुपोषित शिशु, किशोरियों, महिलाओं का चिन्हीकरण कर पोषाहार उपलब्ध कराया जाएगा। नंदा गौरा, पीएम मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट, किशोरी किट के फॉर्म भरे जाएंगे। ग्राम्य विकास द्वारा मनरेगा कार्य की मांग, जॉबकार्ड, भुगतान संबंधी प्रकरणों का निराकरण, पीएमएवाई आवास के आवेदन, एनआरएलएम व रीप में नए सदस्यों को जोड़ना और समूहों को सीसीएल के प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की जाएगी। पंचायत राज द्वारा परिवार रजिस्टर की नकल, जन्ममृत्यु पंजीकरण, सेवायोजन द्वारा रोजगार मेला आयोजन व युवाओं की काउंसलिंग तथा शिक्षा विभाग द्वारा एमडीएम, रमसा व आरटीई से जुड़े विषयों पर सेवाएं प्रदान की जाएगी।

►► शेष पृष्ठ 7 पर

अकिता के हत्यारों को बचाने के खिलाफ सड़कों पर उतरी कांग्रेस

हमारे संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड की बेटा अकिता भंडारी की निर्मम हत्या को तीन साल होने को हैं, लेकिन धामी सरकार आज भी हत्यारों के साथ खड़ी दिखाई देती है, पीड़िता के साथ नहीं। इसी सरकारी संरक्षण, सत्ता की चुप्पी और न्याय की हत्या के खिलाफ आज कांग्रेस के युवा नेता रितेश छेत्री के नेतृत्व में यमुना कॉलोनी चौराहे पर धामी सरकार का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के आवास का घेराव कर यह साफ संदेश दिया कि जो सत्ता में बैठकर चुप है, वह भी इस अपराध में बराबर की भागीदार है।

इस अवसर पर रितेश ने कहा कि आज सवाल सीधे और कठोर हैं। आखिर किसके आदेश पर कंत्रा रिजॉंट को रातों-रात बुलडोजर से मिटया गया? किसके इशारे पर सबूत जलाए गए, गवाह डराए गए और जांच को भटकाया गया? उन्होंने कहा कि क्या धामी सरकार बताएगी कि सत्ता से जुड़े किन चेहरों को बचाने के लिए अकिता के न्याय की बलि दी गई?

कांग्रेस नेत्री गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का नैतिक



दायित्व था कि वे इस हत्याकांड पर सरकार से जवाब मांगतीं, लेकिन उन्होंने भी राजनीतिक चुप्पी को चुना। यह चुप्पी आज जनता के आक्रोश में बदल चुकी है। दसौनी ने पूछा कि जब सत्र न्यायालय में वीआईपी का जिक्र है तो फिर अचानक वीआईपी पर धामी सरकार मौन क्यों हो गई है? उसने जानने की कोशिश क्यों नहीं करी कि अकिता की वॉट्सएप बातचीत में जब किसी वीआईपी का जिक्र है तो फिर वह आखिर कौन है? पुतला दहन में मौजूद वरिष्ठ कांग्रेस नेता संजय शर्मा ने कहा धामी सरकार का पूरा शासनकाल यह साबित करता है कि यह सरकार बेटियों की नहीं, अपराधियों की सरकार है।

पूर्व महानगर अध्यक्ष लाल चंद शर्मा ने कहा कि जब-जब भाजपा सत्ता में

आई है, तब-तब अपराधियों को संरक्षण और पीड़ितों को सिर्फ आशवासन मिले हैं। वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी स्पष्ट ऐलान करती है कि जब तक अकिता भंडारी को पूर्ण न्याय नहीं मिलेगा, जब तक साजिश में शामिल हर प्रभावशाली चेहरा जेल के भीतर नहीं जाएगा, तब तक यह आंदोलन और उग्र, और व्यापक और और निर्णायक होगा। इस मौके पर लोकसेवा आयोग के पूर्व सदस्य संजय शर्मा, नेत्री गरिमा मेहरा दसौनी, पूर्व महानगर अध्यक्ष लाल चंद शर्मा, पार्श्व कोमल वोहरा, संगीता गुप्ता, जगदीश धीमान, राज कुमार जायसवाल राम कुमार थपलियाल, दिनेश कौशल, प्रदीप जोशी, राम भगेल, प्रीतम सिंह आर्य, टोटू त्यागी, पीयूष जोशी, प्रियांशु गौड़, रहमान इत्यादि मौजूद थे।

लिपस्टिक लगाते समय न करें ये 5 गलतियां, बिगड़ सकता है पूरा लुक

लिपस्टिक कई महिलाओं की सुंदरता का अहम हिस्सा है। हालांकि, लिपस्टिक लगाते समय कई महिलाएं कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती हैं, जो उनके लुक को बिगाड़ सकती हैं। इन गलतियों के कारण लिपस्टिक शेड सही तरह से नहीं बैठता या फिर लंबे समय तक नहीं टिकता। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी सामान्य गलतियों के बारे में बताते हैं, जिन्हें लिपस्टिक लगाते समय करने से बचना चाहिए ताकि आपका लुक हमेशा बेहतरीन रहे।

होंठों को साफ न करना- लिपस्टिक लगाने से पहले होंठों की सफाई करना बहुत जरूरी है। अगर आप यह कदम छोड़ देती हैं तो आपका लुक बिगड़ सकता है। सफाई से सूखी त्वचा हटती है, जिससे होंठ चिकने और मुलायम बनते हैं। इसके बाद लिपस्टिक शेड होंठों पर सही तरह से बैठता है और लंबे समय तक टिका रहता है। सफाई से लिपस्टिक का लुक भी बेहतर होता है और आपके होंठों की सुंदरता उभरकर आती है।

बेस न लगाना- बेस का उपयोग करने से आपकी लिपस्टिक लंबे समय तक टिकी रहती है। अगर आप बेस का उपयोग नहीं करती हैं तो आपकी लिपस्टिक जल्दी धुंधली हो सकती है और आपको बार-बार इसे ठीक करने की जरूरत पड़ सकती है। बेस लगाने से आपके होंठों की बनावट समान होती है और लिपस्टिक शेड सही तरह से बैठता है। इससे आपका लुक भी बेहतरीन दिखता है और लिपस्टिक लंबे समय तक टिकी रहती है।

सही शेड का चयन न करना- लिपस्टिक खरीदते समय सही शेड का चयन करना बहुत जरूरी है। कई महिलाएं दुकानदार की सलाह पर बिना सोचे-समझे कोई भी शेड चुन लेती हैं, जो उनके चेहरे पर अच्छा नहीं लगता। हमेशा अपनी त्वचा के रंग और चेहरे की बनावट को ध्यान में रखकर ही लिपस्टिक शेड चुनें। इससे आपका लुक बेहतरीन दिखेगा और आप हमेशा खूबसूरत लगेंगी। सही शेड चुनने से आपकी लिपस्टिक लंबे समय तक टिकी रहती है और आपका चेहरा निखरा हुआ दिखता है।

होंठों की सीमा का ध्यान न रखना- अगर आप चाहती हैं कि आपकी लिपस्टिक पूरे दिन सही रहे तो इसके लिए होंठों की सीमा का ध्यान जरूर रखें। यह आपकी लिपस्टिक को फैलने से रोकता है और आपके होंठों को एक साफ और सुंदर लुक देता है। इसके अलावा इससे आपकी लिपस्टिक लंबे समय तक टिकी रहती है और आपको बार-बार इसे ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे आपके होंठों की बनावट समान होती है और लिपस्टिक शेड सही तरह से बैठता है।

ज्यादा मात्रा में लिपस्टिक लगाना- ज्यादा मात्रा में लिपस्टिक लगाने से आपका लुक ज्यादा बनावटी लग सकता है इसलिए हमेशा थोड़ी मात्रा में ही लिपस्टिक लगाएं। इससे आपका लुक सुंदर और आकर्षक दिखेगा। लिपस्टिक लगाने के बाद अपने होंठों की बनावट को ध्यान में रखते हुए हल्का सा दबाएं ताकि अतिरिक्त तेल हट जाए और लिपस्टिक सेट हो जाए। इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपनी लिपस्टिक को बेहतरीन बना सकती हैं और हमेशा खूबसूरत दिख सकती हैं।

जहां खड़े हैं वहां संभावनाओं के अम्बार

हरीश बड़थवाल

नववर्ष या सांस्कृतिक उत्सवों की रंगरलियां आपको कितना रास आती हैं। यह आपकी मनोदशा पर निर्भर करता है। संभव है आपके अपने भीतर एक अधूरापन सालता रहे। यदाकदा आनंद-विभोर होने के लिए सायास जतन नहीं किए जाएं तो जिंदगी नीरस, उकताऊ और जड़ हो सकती है।

जीवंत रहने और प्रगति के लिए उमंग और हौसले निहायत जरूरी हैं। हमारे अनेक त्योहार जीवन में अनायास पसर जाती एकरसता को निष्क्रिय कर उमंगों-खुशियों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। शुभकामनाएं तभी फलीभूत होती हैं जब ये तहेदिल से निकलें। ऐसा तभी होगा जब हमारे दिल में दूसरों से मेलजोल और उसके सरोकार साझा करने का भाव होगा। सद्चरित्र की खुशबू की भांति हमारी हार्दिक कामनाएं छिपती नहीं हैं। उत्सव प्रतिदिन नहीं आते, किंतु प्रत्येक कार्य या घटना के प्रति सकारात्मक प्रवृत्ति रहेगी तो जीवन में उत्साह और उल्लास का प्रवाह बना रहेगा।

निसंदेह आनंद का रस उन कर्मवीरों के लिए सुरक्षित है जो कुछ नया करने में लगे रहते हैं, आरामपरस्तों के लिए नहीं। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा, 'जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं हैं जो फूलों की छांह के नीचे खेलते और सोते हैं बल्कि फूलों की छांह के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वही भी उन्हीं के लिए है जो दूर रे गिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ, होंठ फटे हुए और सारा बदन पसीने से तर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वही जानता है जो धूप में खूब सूख चुका है।'

नेपोलियन हिल कहते हैं, 'आप जहां खड़े हैं वहीं संभावनाओं का अम्बार है, कोई नया ठौर नहीं तलाशा जाना है, बस कमर कसनी है।' मिशन की साधना में कर्मवीर जोखिम उठाता है। बाधाएं आती हैं और गलतियां भी होती हैं। नए साल की शुभकामना बतौर नील गैमन कहते हैं, 'आगामी साल में नई-नई, चौंकाने वाली गलतियां होने दें; जड़ मत बनिए। यह चिंता छोड़ दें कि प्रेम में, परिवार में, सृजनात्मक क्षेत्र में, कार्यस्थल में, जीवन में, फलां काम बेहतरीन ढंग से नहीं हुआ। गलतियां होने के मायने हैं आप नए प्रयोग कर रहे हैं, नए आयाम तलाश रहे हैं और सबसे बड़ी बात आप कुछ ठोस कर रहे हैं।'

मिनटों में दूर हो जाएगा दांतों का पीलापन, घरेलू नुस्खों को आजमाएं

मुस्कान, स्माइल, हंसी- ये हमारी पर्सनैलिटी का अहम हिस्सा है। लेकिन मुस्कुराते वक्त अगर आपके पीले दांत नजर आए तो आप न सिर्फ हंसी का पात्र बन सकते हैं बल्कि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी पर भी नेगेटिव असर पड़ता है। कई बार रोजाना अच्छी तरह से दांतों को साफ करने के बाद भी दांतों में पीलापन आ जाता है तो कई बार साफ-सफाई और हाइजीन का पूरा ध्यान न रखना भी इसका एक कारण हो सकता है। ऐसे में अगर आपके दांत भी पीले हो गए हैं तो डेंटिस्ट के पास जाकर महंगा ट्रीटमेंट करवाने से पहले एक बार इन घरेलू नुस्खों को अपनाकर देखें। इनसे आप घर बैठे ही बड़ी आसानी से महज 5 मिनट में दांतों का पीलापन दूर कर पाएंगे।

इन वजहों से पीले होते हैं दांत
बहुत से ऐसे कारण जिनकी वजह से दांतों की सफेदी खत्म हो जाती है और दांतों में पीलापन आ जाता है। खाने-पीने की ऐसी कई चीजें हैं जिनसे दांतों पर लगा इनैमल दूधित हो जाता है और दांत पीले नजर आने लगते हैं। इसके अलावा अगर दांत पर प्लाक की परत जम जाए तो इससे भी दांत पीले नजर आने लगते हैं। अधिक चाय या कॉफी का सेवन करना या फिर जो लोग दांतों की सफाई ठीक तरीके से नहीं करते हैं उन्हें भी दांतों से संबंधित अधिक समस्याएं होती हैं।

सरसों का तेल और नमक करें यूज
दांतों का पीलापन दूर करने में सरसों का तेल आपकी मदद कर सकता है। आयुर्वेद भी मानता है कि पीले दांतों की समस्या दूर कर सफेद और चमकदार दांत पाने के लिए सरसों के तेल का इस्तेमाल



करना चाहिए। दांतों को चमकाने के साथ ही मुंह में मौजूद बैक्टीरिया को भी दूर करता है सरसों का तेल। इसके लिए आधा चम्मच सरसों के तेल में चुटकी भर नमक मिलाएं और इस मिश्रण से दांतों पर कुछ देर के लिए मसाज करें। आप चाहें तो उंगली की मदद से दांत और मसूड़ों की मसाज कर सकते हैं या फिर टूथब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। करीब 3 से 5 मिनट तक इस नुस्खे को अपनाएं और फर्क खुद देखें।

सरसों का तेल और हल्दी
आप चाहें तो मोतियों जैसे सफेद और चमकदार दांत पाने के लिए सरसों के तेल के साथ नमक की जगह हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आधा चम्मच हल्दी पाउडर में 1 चम्मच सरसों का तेल मिलाएं और इस पेस्ट को दांतों पर उंगलियों की मदद से धीरे-धीरे रगड़ें। इस मिश्रण का नियमित रूप से इस्तेमाल करें और कुछ ही दिनों में दांतों का पीलापन पूरी तरह से दूर हो जाएगा।

केले का छिलका
दांतों को सफेद करने के लिए आप केले के छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते

हैं। जी हां, केला जितना फायदेमंद फल है, उसका छिलका भी उतना ही फायदेमंद है। केले के छिलके का जो सफेद वाला हिस्सा है उस तरह से छिलके को रोजाना दांतों पर 1 या 2 मिनट तक रगड़ें और उसके बाद हर दिन तकी तरह ब्रश कर लें। केले में मौजूद पोटैशियम, मैग्नीज और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स को दांत सोख लेते हैं। इससे दांत न सिर्फ सफेद बनते हैं बल्कि मजबूत भी होते हैं।

बेकिंग सोडा और नींबू का रस
दांतों को घर पर ही आसानी से सफेद करने का ये एक और नुस्खा है। एक प्लेट में 1 चम्मच बेकिंग सोडा लें और उसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिलाएं। जब तक आपको पेस्ट जैसी कन्सिस्टेंसी न मिल जाए उसमें नींबू का रस मिलाते रहें। अब इस पेस्ट को टूथब्रश पर लगाएं और दांतों पर अच्छी तरह से मसाज करें। इसे करीब 1 मिनट तक दांतों पर लगा रहने दें और उसके बाद मुंह धो लें। बेकिंग सोडा वाले इस पेस्ट को 1 मिनट से ज्यादा दांतों पर लगा न रहने दें वरना दांतों के इनैमल को नुकसान हो सकता है।

पिंपल से छुटकारा पाने के लिए अपनाएं ये घरेलू तरीका

पिंपल की समस्या हम सभी को प्रभावित करती है। लेकिन, कुछ को पिंपल्स की समस्या से जल्द राहत मिल जाती है जबकि कई लोग जीवन भर इस समस्या से जूझते रहते हैं। पिंपल होने की मुख्य वजह तेल-ग्रंथी सीबम में अतिरिक्त स्राव है। जब बेदाग और खूबसूरत चेहरे पर पिंपल की समस्या आ जाए तो दुखी होना स्वाभाविक है। इस आर्टिकल में हम आपको पिंपल की समस्या से निजात पाने के टिप्स बता रहे हैं। पिंपल की

समस्या से निजात पाने के लिए घरेलू उपचार बेहद लाभकारी है। कार्बनिक सेब साइडर सिरका, ग्रीन टी और पुदिने का तेल पिंपल की समस्या से निजात दिलाता है। यहां हम आपको छह घरेलू उपाय बता रहे हैं।

आपको क्या चाहिए?: दो टी बैग से बना एक कप लार्ज ग्रीन टी, कच्चे सेब का सिरका, एक खाली स्प्रे बोतल, पांच बूंद पुदिने का तेल
मैथड : ग्रीन टी को ठंडा होने दें और

इसके बाद अपने स्प्रे बोतल के अंदर 3/4 कप ग्रीन टी भरें। साथ ही में एच चौथाई कच्चे सेब का सिरका मिलाएं। हां ध्या रखें कि बोतल में पांच बूंद से ज्यादा पुदिने का तेल ना मिलाएं। सभी सामग्री को मिलाने के बाद बोतल को कुछ देर तक हिलाए ताकि पुदिने का तेल और सिरका, ग्रीन टी के साथ अच्छी तरह से घुल जाए। इस तरह आपका घरेलू फेसपेक बनकर तैयार हो जाता है। अब आप दिन में दो बार इसे अपने चेहरे पर लगाएं।

बादाम: पाचन शक्ति बढ़ाने में कारगर

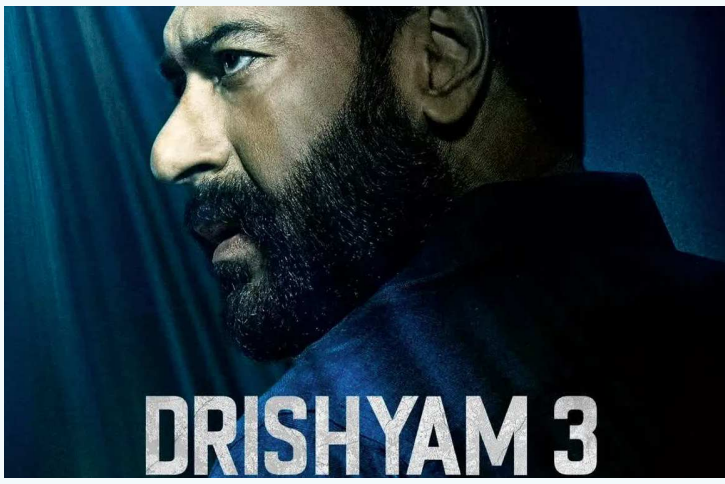


शारीरिक मजबूती के लिए अक्सर लोग बादाम खाने की सलाह देते हैं लेकिन शारीरिक शक्ति बढ़ाने के अलावा बादाम पेट का पाचन तंत्र ठीक रखने में भी कारगर साबित होता है। बादाम में मौजूद फाइबर तत्व हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। बादाम नैचुरल प्रोबायोटिक होता है।

बादाम जो कि एक प्रोबायोटिक है, उसे खाने से शरीर में फायदेमंद बैक्टीरिया बढ़ जाता है, जो पाचन तंत्र के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। साथ ही साथ, ये अच्छे बैक्टीरिया हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाते हैं, और बार-बार होने वाली मौसमी बीमारियों से हमारा

बचाव करते हैं। बादाम में पॉलिफिनॉल होते हैं। ये तत्व एंटी-माइक्रोबायल एजेंट के रूप में काम करते हैं। ये आपको खाने-पीने से पैदा होने वाली कई बीमारियों से सुरक्षा देते हैं और उनका उपचार करने में आपकी मदद करते हैं।

हमारे पाचन तंत्र में ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो शरीर को नुकसानदायक माइक्रोऑर्गेनिज्म से बचाते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थों के ऐसे न पाने वाले हिस्से होते हैं जो बैक्टीरियल ग्रोथ और एक्टिविटी को बढ़ावा देते हैं। शोध अध्ययनों में ये सामने आया है कि बादाम में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो प्रोबायोटिक गुणों को प्रदर्शित करते हैं, और आंतों के अंदर फायदेमंद बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं।



2 अक्टूबर, 2026 को होगी रिलीज दृश्यम 3

अजय देवगन स्टारर आइकॉनिक थ्रिलर फ्रेंचाइजी दृश्यम के अगले चैप्टर का बेसब्री से इंतजार कर रहे फैंस के लिए खुशखबरी है। दृश्यम 3 अब ऑफिशियली बड़े पर्दे के एक कदम और करीब आ गई है। जी हां, क्रिसमस वीक पर मेकर्स ने दृश्यम 3 की रिलीज डेट का एलान किया है। मेकर्स ने एक वीडियो के जरिए इसका एलान किया है। दमदार डायलॉग सुनकर फैंस की उत्सुकता बढ़ गई है।

दृश्यम (2015) और दृश्यम 2 (2022) की जबरदस्त सफलता के बाद, मेकर्स ने अब दृश्यम 3 को लेकर एक अनाउंसमेंट वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने आखिरी इंस्टॉलमेंट के आने की पुष्टि की है। मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर अनाउंसमेंट वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, आखिरी हिस्सा बाकी है। 2 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में।

वीडियो की शुरुआत अजय देवगन और उनके वॉयज ओवर से होती है। वह अपने बहुत पसंद किए जाने वाले किरदार विजय सालगांवकर के रूप में दिखाई देते हैं एक पावरफुल मोनोलॉग दे रहे हैं जो उन सभी सबक को दिखाता है जो उन्होंने सालों में सीखे हैं।

प्रोमो में विजय सालगांवकर कहता है, दुनिया मुझे कई नाम से बुलाती है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पिछले 7 सालों में जो कुछ हुआ, जो कुछ किया, जो कुछ देखा, जो कुछ दिखाया, उससे मुझे एक बात समझ में आ गई है, इस दुनिया में हर किसी का सच अलग है, हर किसी का सही अलग है, मेरा सच, मेरा सही, सिर्फ मेरी फैमिली है।

वीडियो में पिछली फिल्मों के शानदार सीन और नए पलों की झलकियां दिखाई गई हैं, जो इस बात का इशारा करती हैं कि फ्रेंचाइजी अपनी लेयर्ड कहानी और चौकाने वाले ट्विस्ट के एक और राउंड के लिए तैयार है।

स्टार स्टूडियो 18 द्वारा प्रस्तुत फिल्म दृश्यम 3 अभिषेक पाठक ने डायरेक्ट किया है। इसे अभिषेक पाठक ने आमिर कीयान खान और परवेज शेख के साथ मिलकर लिखा है। दृश्यम 3 के हिंदी वर्जन में अजय देवगन और तब्बू के साथ श्रिया सरन, इशिता दत्ता, मृणाल जाधव, कमलेश सावंत और रजत कपूर भी अहम भूमिकाओं में हैं।

विजय सालगांवकर और आईजी मीरा देशमुख के बीच आखिरी टकराव होने वाला है, ऐसे में एक इंटेस और इमोशनल क्लाइमेक्स की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। दृश्यम 3 2 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

जन नायकन का हिंदी टाइटल हुआ रिवील

थलपति विजय काफी समय से अपनी बहुप्रतीक्षित पैन इंडिया फिल्म जन नायकन को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। आज निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर फिल्म का एक पोस्टर जारी किया, जिसमें बाँबी देओल और थलपति विजय भिड़ते नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर के साथ ही निर्माताओं ने इस फिल्म का हिंदी टाइटल रिवील किया है।

फिल्म के इस पोस्टर में विजय और बाँबी देओल के बीच जोरदार टक्कर दिखाई गई है। बैकग्राउंड में आग और तबाही का नजारा है। यह हीरो और विलेन की पुरानी वाली फाइट नहीं, बल्कि विचारधारा और नेतृत्व की जंग का इशारा है। हिंदी टाइटल जन नेता इस थीम को और मजबूत बनाता है। जन नेता जैसे राजनीतिक नाम से फिल्म हिंदी वाले दर्शकों को ज्यादा पसंद आएगी।

विजय गंभीर और मजबूत लग रहे हैं, शांत और सिद्धांतों वाली लीडरशिप दिखा रहे हैं। वहीं बाँबी देओल का लुक दबंग और मिलिट्री स्टाइल वाला है। पोस्टर में हेलीकॉप्टर, डायनामाइट और लड़ाई के संकेत हैं, जो बड़े स्तर की एक्शन और राजनीतिक लड़ाई दिखाते हैं।

यह विजय की आखिरी फिल्म है, इसलिए विदेशों में भी जबरदस्त चर्चा है। ओवरसीज में एडवांस बुकिंग बहुत अच्छी चल रही है। निर्देशक एच. विनोद हैं, जो गंभीर कहानियों के लिए जाने जाते हैं।

संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र का है और कास्ट शानदार है। फिल्म 9 जनवरी 2026 को पोंगल के मौके पर दुनिया भर में रिलीज होगी। यह राजनीतिक और एक्शन से भरपूर अनुभव देने वाली है।

कश्मीरा शाह ने दी ज्यादा पानी पीने की सलाह

अभिनेत्री कश्मीरा शाह ने एक मजेदार वीडियो के जरिए पानी पीने को लेकर अनोखी सलाह दी। उनका अंदाज भले ही हास्य से भरा था, लेकिन उनकी सलाह को आयुर्वेद और विज्ञान भी मानते हैं। वीडियो में मेकअप आर्टिस्ट से बात करते हुए कश्मीरा शाह मजाकिया लहजे में कहती हैं कि रोज ज्यादा पानी पीने से न सिर्फ शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि दिमाग की भी शांत रहता है। उनके मुताबिक, अगर कोई इंसान ज्यादा पानी पीएगा तो उसे बार-बार वॉशरूम जाना पड़ेगा और इस तरह वह फालतू बातचीत से बच जाएगा, जिससे मानसिक शांति मिलेगी। हंसी-मजाक में कही गई ज्यादा पानी पीने की बातों को आयुर्वेद और विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो पानी शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।



आयुर्वेद के अनुसार, पानी को जीवन का आधार माना गया है। पानी शरीर के तीनों दोषों वात, पित्त और कफ को संतुलित रखने में मदद करता है। सही मात्रा में पानी पीने से पाचन ठीक रहता है, शरीर से विषैले तत्व बाहर निकलते हैं और त्वचा में निखार आता है। पानी हमेशा जरूरत के अनुसार और सही समय पर पीना चाहिए, जैसे सुबह उठकर गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है।

विज्ञान भी पानी के महत्व को पूरी तरह मानता है। वैज्ञानिक रिसर्च के मुताबिक, हमारा शरीर लगभग 60 प्रतिशत पानी से बना होता है। पानी ब्लड सर्कुलेशन, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने और दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। पर्याप्त पानी पीने से थकान कम होती है।

है, ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है और मूड भी बेहतर रहता है। यही वजह है कि हल्की डिहाइड्रेशन भी सिरदर्द, चिड़चिड़ापन और थकावट पैदा कर सकती है।

यह समझना भी बेहद जरूरी है कि पानी हमेशा संतुलित मात्रा में ही पीना चाहिए। आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों ही मानते हैं कि जरूरत से ज्यादा पानी पीना भी नुकसानदायक हो सकता है। बहुत अधिक पानी पीने से शरीर में नमक का संतुलन बिगड़ सकता है, जिसे मेडिकल भाषा में वॉटर इंटॉक्सिकेशन कहा जाता है। इसलिए विशेषज्ञ यही सलाह देते हैं कि इंसान को अपनी प्यास, मौसम, शारीरिक गतिविधि और उम्र के अनुसार पानी पीना चाहिए, न कि किसी तय संख्या के दबाव में।

मानसिक सेहत की बात करें, तो पानी का सीधा संबंध दिमाग से भी है। जब शरीर हाइड्रेटेड रहता है, तो दिमाग बेहतर तरीके से काम करता है।

इससे तनाव कम महसूस होता है और मन ज्यादा शांत रहता है। यही वजह है कि कई डॉक्टर और योग विशेषज्ञ दिनभर थोड़ा-थोड़ा पानी पीते रहने की सलाह देते हैं, ताकि शरीर और मन दोनों संतुलन में रहें।

इससे तनाव कम महसूस होता है और मन ज्यादा शांत रहता है। यही वजह है कि कई डॉक्टर और योग विशेषज्ञ दिनभर थोड़ा-थोड़ा पानी पीते रहने की सलाह देते हैं, ताकि शरीर और मन दोनों संतुलन में रहें।

शाहिद कपूर ओ रोमियो से तहलका मचाने के लिए तैयार



बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर की पिछली रिलीज फिल्म देवा दर्शकों का दिल

जीतने में नाकामयाब रही। अब विशाल भारद्वाज के साथ उनकी जोड़ी फिर से धमाका करने के लिए तैयार है। दोनों की अगली फिल्म ओ रोमियो का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है जो फिलहाल अपने शूटिंग चरण में है। खुद शाहिद फिल्म के लिए उतावले हैं, और यही वजह है कि नए साल का जश्न होने के बावजूद उन्होंने शूटिंग जारी रखने का मन बनाया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, ओ रोमियो की शूटिंग का आखिरी चरण 28 दिसंबर से शुरू होगा। नए साल के जश्न के लिए ब्रेक लेने की संभावना नहीं है, क्योंकि निर्माता मुंबई में 10 दिनों की पैच शूटिंग शुरू कर सकते हैं। इस चरण में एक्शन सीक्वेंस शामिल होंगे जिसे फिल्माने के लिए शाहिद जुटेंगे।

सूत्र ने कहा, यह टुकड़ों में शूट किया जा रहा है, जिसमें कुछ एक्शन और संवाद प्रधान दृश्य शामिल हैं।

सूत्र ने आगे बताया कि नए साल के संक्षिप्त अवकाश के बाद, जनवरी 2026 में 8 दिनों शूटिंग के साथ प्रोडक्शन फिर से शुरू होने की उम्मीद है। निर्माताओं की कोशिश है कि फिल्म तय समय पर यानी, 13 फरवरी, 2026 को रिलीज हो जाए। हाई-ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर फिल्म ओ रोमियो का निर्माण नाडियाडवाला प्रैंडसन एंटरटेनमेंट बैनर के तहत किया जा रहा है। इसमें तृति डिमरी, रणदीप हुड्डा और नाना पाटेकर भी अहम किरदार में हैं।

वीबी-जी राम जी एक्ट 2025 संरचनात्मक कमियों को ठीक करता है

शिवराज सिंह चौहान

भारत के राष्ट्रपति ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) एक्ट, 2025 को मंजूरी दे दी है, जिससे कानूनी मजदूरी रोजगार गारंटी को 125 दिन तक बढ़ाया गया है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत के लिए सशक्तिकरण, तालमेल और संतुष्टि-आधारित डिलीवरी के जरिए ग्रामीण आजीविका को मजबूत किया गया है।

कुछ लोगों द्वारा गलत समझा जाना

फिर भी, जैसे ही वीबी-जी राम जी एक्ट लागू होता है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ ऐसी धारणाएँ बनाई हैं जो ध्यान से जाँच करने पर सही नहीं ठहरतीं। यह दावा किया जा रहा है कि रोजगार गारंटी कमजोर हो गई है, कि बिना सलाह-मशविरा के विकेंद्रीकरण और मांग-आधारित अधिकारों को कमजोर किया गया है, और यह कि यह सुधार एक तरह की वित्तीय कटौती है जिसे पुनर्गठन के रूप में छिपाया गया है। इनमें से हर दावा एक्ट के मूल और इरादे को गलत समझने पर आधारित है।

इस गलतफहमी की वजह एक गहरी वैचारिक गलती है - यह मानना कि कल्याण और विकास एक-दूसरे के विरोधी विकल्प हैं। नया फ्रेमवर्क इसके उलट समझ पर आधारित है- कि कल्याण, जो बेहतर कानूनी आजीविका गारंटी पर आधारित है, और विकास, जो टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर आधारित है, एक-दूसरे को मजबूत करते हैं। इनकम सपोर्ट, संपत्ति निर्माण, कृषि स्थिरता और लंबे समय तक ग्रामीण प्रोडक्टिविटी को एक-दूसरे का विकल्प मानने के बजाय एक निरंतर प्रक्रिया के

रूप में देखा जाता है। यह सिर्फ कोरी बातें नहीं हैं, बल्कि एक ऐसा तरीका है जो कानूनी डिजाइन में शामिल है।

यह सुझाव कि रोजगार के कानूनी अधिकार को कमजोर किया गया है, गलत है। यह एक्ट रोजगार गारंटी के कानूनी और न्यायोचित स्वरूप को बनाए रखता है, साथ ही इसे लागू करने की क्षमता को भी मजबूत करता है। इसे कम करने के बजाय, अधिकार को 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। प्रक्रियात्मक अयोग्यता के उन प्रावधानों को हटा दिया गया है जो पहले बेरोजगारी भत्ते को व्यवहार में खत्म कर देते थे, और समय-सीमा वाले शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत किया गया है। यह सुधार सीधे तौर पर कानूनी बादे और ज़मीनी हकीकत के बीच लंबे समय से चली आ रही खाई को दूर करता है।

यह भी तर्क दिया जाता है कि टॉप-डाउन प्लानिंग के पक्ष में डिमांड-बेस्ड रोजगार को छोड़ दिया गया है। यह एक गलत सोच पर आधारित है। काम की डिमांड मजदूरों से ही आती रहती है। जो बदलता है वह यह है कि अब डिमांड को तभी पूरा नहीं किया जाता जब परेशानी शुरू हो जाती है। पहले से ही काम की प्लानिंग करके, गाँव लेवल पर सबकी भागीदारी वाली प्लानिंग से, यह सुधार यह पक्का करता है कि जब मजदूर रोजगार ढूँढते हैं, तो काम असल में उपलब्ध हो, न कि एडमिनिस्ट्रेटिव तैयारी की कमी के कारण मना कर दिया जाए। इस मायने में, प्लानिंग डिमांड को दबाती नहीं है; यह उसे

लागू करती है।

केंद्रीकरण के आरोप में कानून के ढाँचे को नज़रअंदाज़ किया जाता है। ग्राम पंचायतें प्राइमरी प्लानिंग और लागू करने वाली



अर्थो रिटी बनी हुई हैं, और ग्राम सभाओं के पास लोकल प्लान पर मंजूरी देने की शक्तियाँ हैं। जो बदला है वह यह है कि डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग अब अचानक या कभी-कभी नहीं होती, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड और सबकी भागीदारी वाली प्रक्रिया के रूप में संस्थागत हो गई है। विकसित ग्राम पंचायत प्लान को ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय लेवल पर इकट्ठा किया जाता है ताकि सभी सेक्टरों में कोऑर्डिनेशन, तालमेल और पारदर्शिता हो सके, न कि लोकल प्राथमिकताओं को नज़रअंदाज़ किया जाए। जो केंद्रीकृत है वह तालमेल है; फ़ैसले लेने का अधिकार लोकल ही रहता है। यह डिसेंट्रलाइजेशन को कमजोर किए बिना बिखराव को ठीक करता है।

यह दावा कि सुधार बिना किसी सलाह-मशविरा के लागू किए गए, रिकॉर्ड के हिसाब से बिल्कुल गलत है। बिल से पहले राज्य सरकारों के साथ बड़े पैमाने पर बातचीत, टेक्निकल वर्कशॉप और कई स्टेकहोल्डर के साथ चर्चा हुई थी। मुख्य डिजाइन फीचर्स - गाँव की प्लानिंग स्ट्रक्चर, कन्वर्जेंस मैकेनिज्म और डिजिटल गवर्नेंस सिस्टम - राज्यों से मिले फीडबैक और सालों के इम्प्लीमेंटेशन से मिले सबक से तैयार किए गए थे।

आवंटन में वृद्धि, समानता

यह व्यापक धारणा कि पिछले एक दशक में रोजगार गारंटी को व्यवस्थित रूप से कमजोर किया गया, तथ्यों से मेल नहीं खाती। बजटीय आवंटन 2013-14 में 233,000 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 286,000 करोड़ हो गया। सृजित मानव दिवस 2013-14 तक की अवधि में 1,660 करोड़ से बढ़कर उसके बाद 3,210 करोड़ हो गए। जारी केंद्रीय निधि 22.13 लाख करोड़ से बढ़कर 28.53 लाख करोड़ हो गई, और पूरे किए गए कार्य 153 लाख से बढ़कर 862 लाख हो गए। महिलाओं की भागीदारी 48 प्रतिशत से बढ़कर 56.73 प्रतिशत हो गई। अब 99 प्रतिशत से अधिक फंड ट्रांसफर ऑर्डर समय पर जेनरेट होते हैं, और लगभग 99 प्रतिशत सक्रिय श्रमिक आधार पेमेंट ब्रिज से जुड़े हुए हैं। ये रुझान निरंतर प्रतिबद्धता और बेहतर डिलीवरी की ओर इशारा करते हैं, न कि उपेक्षा की ओर।

हालांकि, समय के साथ यह स्पष्ट हो गया कि कार्यान्वयन के अनुभव ने पहले के ढाँचे में ही संरचनात्मक कमजोरियों को भी उजागर किया था - सामयिक रोजगार, बेरोजगारी भत्ते की कमजोर

प्रवर्तनीयता, खंडित संपत्ति निर्माण और दोहराव और फर्जी प्रविष्टियों की लगातार गुंजाइश। ये कमजोरियाँ सूखे के वर्षों, प्रवासन में वृद्धि और कोविड-19 महामारी जैसी व्यवधान की अवधि के दौरान ज़मीनी स्तर पर दिखाई दे रही थीं।

नए एक्ट के तहत फिस्कल रिस्ट्रिक्टिंग को भी गलत तरीके से जिम्मेदारी छोड़ने जैसा बताया जा रहा है। केंद्र सरकार का योगदान बढ़ रहा है - केंद्र के हिस्से का प्रावधान 286,000 करोड़ से बढ़कर लगभग 295,000 करोड़ हो गया है, जो ग्रामीण रोजगार के लिए लगातार और बढ़े हुए समर्थन को दिखाता है। 60-40 फंडिंग मॉडल केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लंबे समय से चले आ रहे स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जबकि उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों और जम्मू और कश्मीर को 90-10 का अलग अनुपात दिया गया है। फिस्कल विड्रॉल का संकेत देने के बजाय, यह फ्रेमवर्क साझा जिम्मेदारी और जवाबदेही को मजबूत करता है।

नियम-आधारित नॉर्मेटिव एलोकेशन के माध्यम से इकटिरी सुनिश्चित की जाती है, जिसमें राज्यों के अनुसार एलोकेशन नियमों में बताए गए ऑब्जेक्टिव पैरामीटर पर तय किए जाते हैं। राज्यों को सिर्फ लागू करने वाली एजेंसियों के रूप में नहीं, बल्कि विकास में पार्टनर के रूप में माना जाता है, जिन्हें कानूनी ढाँचे के भीतर अपनी योजनाओं को नोटिफाई करने और लागू करने का अधिकार है। फ्लेक्सिबिलिटी को साफ तौर पर बनाए रखा गया है- प्राकृतिक आपदाओं या अन्य असाधारण स्थितियों के दौरान, राज्य विशेष छूट की सिफारिश कर सकते हैं, जिसमें अनुमत कार्यों का विस्तार और रोजगार में अस्थायी वृद्धि शामिल है। इस प्रकार, नियम-आधारित एलोकेशन और प्रासंगिक फ्लेक्सिबिलिटी को सहकारी संघवाद के अनुरूप संतुलित किया गया है।

शामिल होंगे और इस दौरान कोई काम नहीं किया जाएगा। कृषि-जलवायु स्थितियों के आधार पर जिलों, ब्लॉकों या ग्राम पंचायतों के लेवल पर अलग-अलग नोटिफिकेशन जारी किए जा सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि बढ़ी हुई रोजगार गारंटी कृषि कार्यों को पूरा करे।

यूपीए का रिकॉर्ड अपने पहले कार्यकाल से ही, कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस (यूपीए) सरकार एमजीएनआरईजीए के तहत वादों को पूरा करने में नाकाम रही। जहाँ कांग्रेस के घोषणापत्र में कम से कम 100 दिन का काम 100 रुपये प्रतिदिन की असली मजदूरी पर देने का वादा किया गया था, वहीं सरकार ने 2009 में ही मजदूरी को 100 रुपये पर सीमित कर दिया और महंगाई और बढ़ते ग्रामीण संकट को नज़रअंदाज़ करते हुए इसे सालों तक फ्रीज़ रखा। केंद्र सरकार ने खुले तौर पर माना कि राज्य इस योजना के तहत मनमाने तरीके से काम कर रहे थे और अंधाधुंध बढ़ोतरी

के लिए राज्य सरकारों को दोषी ठहराकर मजदूरी फ्रीज़ को सही ठहराया। यह स्वीकारोक्ति अपने आप में एक गंभीर शासन विफलता को उजागर करती है- कांग्रेस के नेतृत्व वाला केंद्र अपनी ही राज्य सरकारों को नियंत्रित करने में असमर्थ था, जिससे एमजीएनआरईजीए दुरुपयोग, फर्जी जॉब कार्ड और वित्तीय लीकेज के प्रति संवेदनशील हो गया।

यूपीए के दूसरे कार्यकाल में इस योजना के प्रति प्रतिबद्धता में लगातार गिरावट देखी गई। राज्यों से बढ़ती मांग के बावजूद, बजटीय आवंटन 2010-11 में 240,100 करोड़ से घटकर 2012-13 तक 33,000 करोड़ कर दिया गया। 2013 में एक संसदीय जवाब में, राज्य मंत्री राजीव शुक्ला ने स्वीकार किया कि एमजीएनआरईजीए के तहत रोजगार 2010-11 में 7.55 करोड़ श्रमिकों से घटकर नवंबर 2013 तक सिर्फ 6.93 करोड़ रह गया था। फंड जारी करने में देरी, भुगतान में पारदर्शिता की कमी और प्रशासनिक उदासीनता ने श्रमिकों को रोजगार मांगने से हतोत्साहित किया, जिससे सीधे तौर पर अधिनियम के तहत दी गई कानूनी गारंटी कमजोर हुई।

कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की 2013 की रिपोर्ट ने यूपीए के सालों में मनरेगा की असली हालत को सामने ला दिया था। इसने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन को उजागर किया- 4.33 लाख से ज्यादा नकली या खराब जॉब कार्ड, बिना हिसाब-किताब के पैसे निकालने और अनियमित काम से हजारों करोड़ रुपये का नुकसान, 23 राज्यों में मजदूरी में देरी या इनकार, और भारत की आधी से ज्यादा ग्राम पंचायतों में खराब रिकॉर्ड-कीपिंग। जिन राज्यों में ग्रामीण गरीबों की संख्या सबसे ज्यादा थी - बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र - उन्होंने आवंटित फंड का सिर्फ 20 प्रतिशत ही इस्तेमाल किया, जिससे यह साबित होता है कि यह योजना ठीक वही फेल हो गई जहाँ इसकी सबसे ज्यादा ज़रूरत थी।

बहस को कल्याण और विकास के बीच चुनाव के रूप में पेश करना एक झूठा विरोधाभास है। कल्याण, जब गारंटीशुदा आजीविका पर आधारित हो, और विकास, जब टिकाऊ ग्रामीण बुनियादी ढाँचे और उत्पादकता पर आधारित हो, तो ये प्रतिस्पर्धी लक्ष्य नहीं बल्कि एक-दूसरे पर निर्भर लक्ष्य हैं। असली फैसला यह था कि क्या एक ऐसे फ्रेमवर्क को फ्रीज़ किया जाए जो अक्सर उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं देता था, या इसे एक आधुनिक, लागू करने योग्य और एकीकृत रोजगार गारंटी में सुधारा जाए जो विकास के माध्यम से कल्याण को आगे बढ़ाए। नया अधिनियम काम के कानूनी अधिकार को बरकरार रखता है, अधिकारों का विस्तार करता है, श्रमिकों की सुरक्षा को मजबूत करता है, और सालों के कार्यान्वयन से सामने आई संरचनात्मक कमजोरियों को ठीक करता है। यह तोड़फोड़ नहीं है, बल्कि अनुभव पर आधारित नवीनीकरण की एक प्रक्रिया है।

लेखक भारत सरकार में कृषि और किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री हैं।

सू-दोकू क्र.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | 4 | | 7 | |
| | 6 | 9 | | 2 | | 1 |
| | 7 | | 6 | | 8 | 2 |
| 1 | | | | | | 8 |
| | 8 | | 5 | | 2 | 3 |
| 3 | 2 | | 4 | | 1 | |
| | 3 | 2 | | | 4 | |
| | 8 | | 1 | 6 | | 7 |
| 9 | | 4 | | | | 2 |

नियम

- कुल 81 वर्ग हैं, जिसमें 9 वर्गों का एक खंड बनाता है।
- हर खाली वर्ग में 1 से 9 के बीच का कोई एक अंक भर सकते हैं।
- बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम, कतार और खंड में 1 से 9 अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते हैं।

सू-दोकू क्र 30 का हल

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 6 | 8 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 |
| 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 6 | 3 | 9 |
| 7 | 1 | 4 | 6 | 9 | 3 | | 2 | 5 |
| 1 | 8 | 9 | 3 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 |
| 2 | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 1 | 9 | 3 |
| 5 | 4 | 3 | 9 | 1 | 2 | 7 | 8 | 6 |
| 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 9 | 5 | 1 | 8 |
| 9 | 5 | 1 | 7 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 |
| 4 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 6 | 7 |



जिलाधिकारी ने अनेक प्रकरणों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा बैठक की

हमारे संवाददाता

अल्मोड़ा। जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने आज जिला कार्यालय में आयोजित स्टाफ बैठक की अध्यक्षता करते हुए जनपद की राजस्व वसूली, वादों का निस्तारण समेत अनेक प्रकरणों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व वसूली को प्राथमिकता देते हुए निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति सुनिश्चित की जाए तथा इस कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने विभिन्न लिखित राजस्व एवं अन्य वादों की समीक्षा करते हुए उनके त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वादों का शीघ्र निस्तारण आमजन को समय पर न्याय दिलाने के साथ-साथ प्रशासनिक कार्यप्रणाली को भी सुदृढ़ बनाता है। जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों के सत्यापन एवं पंजीकरण कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र किसानों का शत-प्रतिशत सत्यापन सुनिश्चित किया जाए, ताकि कोई भी पात्र किसान योजना के लाभ से वंचित न रहे। साथ ही अपात्र व्यक्तियों को सूची से हटाने एवं अभिलेखों को अद्यतन रखने के भी निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने कहा कि बीते समय में घटित आपदाओं से प्रभावित लोगों को नियमानुसार शत प्रतिशत मुवावजा वितरण की कार्यवाही कर ली जाए। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन से संबंधित गाइडलाइन का सभी अधिकारी विस्तार से अध्ययन करें तथा आपदा से प्रभावित जनोपयोगी परिसंपत्तियों के नियमानुसार आगणन बनाकर प्रस्तुत किए जाए। उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं के पश्चात होने वाली मजिस्ट्रियल जांचों में तेजी लाई जाए।

जिलाधिकारी ने कहा कि लोगों के लिए पारदर्शी और निष्पक्ष प्रणाली सुनिश्चित कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके लिए अधिकारी अपनी अपनी भूमिकाओं का शत प्रतिशत निर्वहन करें। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए शासन की योजनाओं एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का आह्वान किया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी रामजी शरण शर्मा, अपर जिलाधिकारी युक्ता मिश्र, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रानीखेत गौरी प्रभात, उपजिलाधिकारी सदर संजय कुमार, द्वाराहाट सुनील कुमार राज समेत अन्य उपजिलाधिकारी वचुंअल जुड़े रहे साथ ही अन्य संबंधित भी उपस्थित रहे।

जमीन दिलाने के नाम पर ठगे 11 लाख रुपये

देहरादून (सं)। जमीन दिलाने के नाम पर 11 लाख रुपये की ठगी करने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार नथुवाला निवासी नीलम ने रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी पहचान बालावाला निवासी सुनील कोठारी से हुई। सुनील ने उसको जमीन दिलाने का झांसा देकर 11 लाख रुपये ठग लिये।

5 जनवरी को कालसी में आयोजित...

◀ पृष्ठ 2 का शेष

खाद्य विभाग राशन कार्डों का सत्यापन, संशोधन व दुरस्तीकरण व राज्य खाद्य योजना के राशन कार्ड निर्गत करेगा। कृषि व उद्यान विभाग कीटनाशक दवाओं, बीज, लघु यंत्रों का वितरण एवं कृषकों की समस्या का समाधान करेंगे। सहकारिता, रेशम, मत्स्य, दुग्ध विभाग खाद्य बीज की उपलब्धता, समितियों के सदस्य बनने, केसीसी लाभार्थियों का चयन करेंगे। विद्युत व पेयजल विभाग विद्युत बिल, पेयजल बिलों का सुधार, भुगतान, नए कनेक्शन वितरण करेंगे। लोनिवि, एनएचएआई, पीएमजीएसवाई द्वारा राजमार्ग, राज्य मार्ग, ग्रामीण मार्गों से संबंधित समस्याओं का समाधान तथा सिंचाई विभाग द्वारा सिंचन क्षमता विस्तार संबंधी विषयों पर कार्रवाई की जाएगी। उद्योग व खादी ग्रामोद्योग द्वारा स्वरोजगार आवेदन प्राप्त करना, प्रशिक्षण तथा राजस्व विभाग द्वारा नए आधार कार्ड बनाने, आधार संशोधन के साथ आय, जाति चरित्र, स्थायी निवास, निर्विवाद उत्तराधिकार के मामलों का निस्तारण किया जाएगा। लीड बैंक द्वारा वंचित परिवारों का शत प्रतिशत बैंक लिंकेज, पीएम जीवन ज्योति, पीएम जीवन सुरक्षा योजना, सीसीएल व स्वरोजगार योजनाओं के आवेदनों का निस्तारण किया जाएगा। पर्यटन द्वारा होम स्टे, वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना के लाभार्थियों का चयन तथा श्रम विभाग द्वारा श्रमिक कार्ड बनाने, रिन्युअल करने, पंजीकृत श्रमिकों को सामग्री वितरण का काम किया जाएगा। शिविर में यूसीसी के तहत पंजीकरण भी किए जाएंगे। जिलाधिकारी ने क्षेत्रीय जनमानस से संचालित विभिन्न सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करने एवं अपनी समस्या का निराकरण करने हेतु आयोजित शिविर में प्रतिभाग करने की अपील की है।

हरिद्वार पुलिस का वर्ष 2025 रिपोर्ट कार्ड: सलारवों के पीछे पहुंचे कई बड़े धुरंधर

हमारे संवाददाता

हरिद्वार। धर्मनगरी हरिद्वार की पुलिस ने बीते वर्ष 2025 में कप्तान प्रमोद सिंह डोबाल के नेतृत्व में अपराध व अपराधियों के खिलाफ कड़ी व त्वरित कार्यवाहियों की गयी है। जिनमें कई ब्लाइंड मर्डर के खुलासे सहित कई धुरंधरों को सलाखों के पीछे भेजा गया है। वहीं नशे के खिलाफ चलाये गये अभियान में पुलिस ने 585 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर नशे के साम्राज्य को भी ध्वस्त किया गया है।

पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि साईबर सेल हरिद्वार ने वर्ष 2025 में प्राप्त हुए साइबर ठगी की कुल 5781 प्राप्त शिकायतों में से 4356 शिकायतों को निस्तारित करते हुए फ्रॉड का शिकार बने लोगों की कुल 12745864/- (एक करोड़ सत्ताईस लाख पैतालिस हजार आठ सौ चौसठ रुपये) वापस दिलाए। इस दौरान सभी थानों एवं साईबर सेल ने मिलकर सीआईआईआर पोर्टल की मदद से कुल 1088 मोबाइल फोन रिकवर किए तथा उक्त मोबाइलों को उनके मालिकों को लौटाया। रिकवर किए गए मोबाइल फोनों की बाजार कीमत 16500000/- (एक करोड़ पैंसठ लाख रुपये) के करीब आंकी गई। गुमशुदगी/अपहरण के कुल 1320 मामलों में पुलिस ने कड़ी मशक्कत करते हुए 1082 गुमशुदाओं/अपहृत को सकुशल बरामद किया। इनमें 263 किशोरियां, 105 किशोर, 420 महिलाएं



तथा 294 पुरुष शामिल हैं। ऑपरेशन कालनेमी के तहत हरिद्वार पुलिस ने वर्ष 2025 में कुल 5300 व्यक्तियों का सत्यापन करते हुए 508 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया तथा 307 आरोपितों के खिलाफ चालानी/नोटिस की कार्यवाही की गई। इनमें विवाह के नाम पर छल, पहचान, धर्म, जाति, वैवाहिक स्थिति छिपाकर उछेरित करने के 4 तथा फर्जी सौशल मीडिया प्रोफाइल, फिशिंग आदि साईबर धोखाधड़ी के 26 आरोपी शामिल हैं।

गौवंश तस्करी और गौहत्या से जुड़े तत्वों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए उत्तराखण्ड गौ संरक्षण अधिनियम के तहत बीते वर्ष कुल 400 आरोपितों के खिलाफ 127 मुकदमें दर्ज किए गए। 48 पशु बरामद करने के साथ 15768 किलोग्राम गौमांस बरामद किया गया। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत 116 आरोपित के खिलाफ 65 मुकदमें दर्ज करते हुए 66 जीवित पशु व 3102

किलोग्राम भैंसवंशीय मांस बरामद किया गया। घटित अपराधों पर ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए पुलिस ने इस दौरान हत्या के 62 मुकदमों का खुलासा करते हुए कुल 104 आरोपितों को गिरफ्तार किया। समय-समय पर चलाए गए चैकिंग अभियानों के दौरान अवैध अस्त्राह के 393 आरोपित को गिरफ्तार कर 2 डीबीबीएल राइफल, 6 एसबीबीएल, 195 तमंचे, 2 रिवाल्वर, 12 पिस्टल, 244 कारतूस तथा 364 चाकू बरामद किए।

नशा तस्करी पर लगाम लगाने के लिए निरंतर प्रयास करते हुए हरिद्वार पुलिस ने वर्ष 2025 में 585 तस्करों को गिरफ्तार करते हुए एनडीपीएस एक्ट में 536 मुकदमें दर्ज किये। इस दौरान 16.83 किलोग्राम चरस, 5.53 किलोग्राम स्मैक, 1.18 किलोग्राम अफीम, 243.94 किलोग्राम गांजा, 14075 नशीली गोलिएं, 3906 नशीले इंजेक्शन, 353843 कैप्सूल व 326 सीरप बरामद किया गया। उक्त बरामद नशीले पदार्थों की बाजार कीमत 179300000/- (सत्रह करोड़ तेरानवे लाख) के करीब आंकी गई है। शराब तस्करों के खिलाफ कार्यवाही के दौरान हरिद्वार पुलिस ने 988 आरोपितों को गिरफ्तार करते हुए 976 मुकदमें दर्ज किए गए। इस दौरान बरामदगी 12392 बोतल देशी शराब, 3523 बोतल अंग्रेजी शराब, 2877 लीटर कच्ची शराब, 760 बीयर व 8 भट्टी एवं अन्य उपकरण बरामद किए गए।

फरार चल रहा वारंटी गिरफ्तार

हमारे संवाददाता

चमोली। गैर-जमानती वारंटों/कुर्की वारंटों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत पुलिस ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कर्णप्रयाग द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट/कुर्की वारंट से संबंधित आरोपी की गिरफ्तारी हेतु प्रभावी कार्रवाई की गई है।

पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है। इस अभियान के अंतर्गत फौजदारी मुकदमा संख्या 41/25, धारा 138 एनआई एक्ट में फरार आरोपी नरेन्द्र सिंह पुत्र गंगा सिंह, निवासी गौणा, तहसील एवं जनपद चमोली, उम्र 29 वर्ष को सर्विलांस की सटीक मदद से लोकेशन ट्रेस कर आज उसके वर्तमान निवास स्थान नियर लॉ कॉलेज, गोपेश्वर से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूर्ण कर उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आरोपी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक सतेन्द्र बुटोला (एसओजी प्रभारी), अपर उपनिरीक्षक राजीव कुमार व हेड कांस्टेबल भगत लाल शामिल रहे।

उत्तराखंड की पहली म्यूजिकल सांस्कृतिक फिल्म का भव्य शुभारंभ

हमारे संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड सिनेमा के इतिहास में एक ऐतिहासिक पल जुड़ गया है। सिनेफिक्शन इंटरटेन्मेंट उत्तराखंड की पहली म्यूजिकल कल्चरल फिल्म का निर्माण करने जा रही है, जिसकी 1 जनवरी 2026 को विधिवत शुरुआत हुई है।

इस महत्वाकांक्षी फिल्म का निर्देशन शुभम सेमवाल का रहे है जबकि फिल्म की कहानी प्रसिद्ध विद्वान आचार्य डॉ. कृष्णानंद नौटियाल द्वारा लिखित "चरव्यू" पर आधारित है। संगीत निर्देशन की जिम्मेदारी अखिल मौर्य निभा रहे हैं। वहीं शैलेश नौटियाल फिल्म में एसोसिएट डायरेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म के निर्माता हैं अनिरुद्ध सिंह बघेल जो उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को सिनेमा के माध्यम से नई पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।



फिल्म का मुहूर्त केदारनाथ की विधायक श्रीमती आशा नौटियाल के देहरादून स्थित आवास पर संपन्न हुआ। आशा नौटियाल ने फिल्म का विधिवत 'क्लैप' किया और पूरी टीम को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने कहा कि ऐसी सांस्कृतिक फिल्में उत्तराखंड की परंपराओं और लोकसंस्कृति को वैश्विक मंच पर पहुँचाने का सशक्त

माध्यम बनेंगी। इस अवसर पर केदारघाटी मंडाण के संरक्षक नरेंद्र रैथान भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उनकी मौजूदगी ने मुहूर्त समारोह को और भी गरिमामय बना दिया। यह फिल्म उत्तराखंड की लोकसंस्कृति, संगीत और परंपराओं को दर्शकों के दिलों से जुड़ने का कार्य करेगी।

परिवार रजिस्टर में अनियमितताओं पर प्रदेशव्यापी जांच के निर्देश

संवाददाता
देहरादून। परिवार रजिस्टर में अनियमितताओं को देख मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देशित किया कि प्रदेश के सभी जिलों में उपलब्ध परिवार/कुटुंब रजिस्ट्रों की प्रतियां तत्काल संबंधित जिलाधिकारी (डीएम) के पास सुरक्षित रखी जाएं, जिससे अभिलेखों में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की संभावना समाप्त हो।

आज यहां उत्तराखंड में परिवार रजिस्टर में सामने आ रही गंभीर अनियमितताओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य स्तर पर व्यापक, निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि प्रदेश के सभी जिलों में उपलब्ध परिवार/कुटुंब रजिस्ट्रों की प्रतियां तत्काल संबंधित जिलाधिकारी (डीएम) के पास

सुरक्षित रखी जाएं, जिससे अभिलेखों में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की संभावना समाप्त हो। साथ ही, परिवार रजिस्ट्रों की गहन जांच सीडीओ/एडीएम स्तर पर कराए जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में यह भी तय किया गया कि जांच का दायरा वर्ष 2003 से अब तक रखा जाएगा, ताकि पूर्व वर्षों में हुई संभावित अनियमितताओं की भी पहचान हो सके। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नाम दर्ज कराने वालों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय व कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अवगत कराया कि परिवार रजिस्टर का पंजीकरण एवं प्रतिलिपि सेवाएं पंचायत राज (कुटुंब रजिस्ट्रों का अनुरक्षण) नियमावली, 1970 के अंतर्गत संचालित होती हैं। नियमों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले प्रत्येक परिवार का नाम परिवार/कुटुंब रजिस्टर में दर्ज होना अनिवार्य है। वर्तमान प्रविष्टियों के शुद्धिकरण तथा नए नामों को जोड़ने की



प्रक्रिया का प्रावधान भी नियमावली में निहित है, जिसे अब और अधिक सख्त व पारदर्शी बनाए जाने की तैयारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज करने का अधिकार सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को प्राप्त है, जबकि अपील का अधिकार उप जिलाधिकारी (एसडीएम) के पास निहित

है। वर्तमान में परिवार रजिस्टर से संबंधित त सेवाएं अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। बैठक में यह तथ्य भी सामने आया कि बीते वर्षों में राज्य की सीमा से लगे मैदानी जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में अनधिकृत बसावट के आधार पर परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज होने से जनसांख्यिकीय संतुलन प्रभावित होने की आशंका रही है। इसी पृष्ठभूमि में सरकार द्वारा परिवार रजिस्टर से संबंधित नियमावली में आवश्यक संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई है। पंचायती राज विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में परिवार रजिस्टर से जुड़ी सेवाओं हेतु प्रदेशभर में बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए। 01 अप्रैल से 31 दिसंबर 2025 के बीच नए परिवार जोड़ने के लिए 2,66,294 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 2,60,337 आवेदन स्वीकृत तथा 5,429 आवेदन नियमों के उल्लंघन एवं अपूर्ण दस्तावेजों के कारण निरस्त किए गए। विशेषज्ञों के अनुसार निरस्त

आवेदनों की संख्या फर्जी प्रविष्टियों की आशंका की ओर संकेत करती है, जिसके दृष्टिगत प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सीमावर्ती जिलों सहित प्रदेश के सभी जिलों में समान रूप से जांच की जाए, ताकि किसी भी क्षेत्र में भेदभाव या ढिलाई न हो। भविष्य में परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज किए जाने की प्रक्रिया को स्पष्ट नीति के अंतर्गत नियंत्रित कर कैबिनेट में प्रस्तुत किए जाने का भी निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि सरकारी अभिलेखों से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस उच्चस्तरीय बैठक में सचिव गृह शैलेश बागौली, डीजीपी दीपम सेठ, डीजीपी इंटेल्जेंस अभिनव कुमार, विशेष सचिव पंचायती राज डॉ. पराग धकाते तथा निदेशक पंचायती राज निधि यादव उपस्थित रहे।

मकान का ताला तोड़ जेवरात व नगदी चोरी

संवाददाता
देहरादून। चोरों ने मकान का ताला तोड़ वहां से जेवरात व नगदी चोरी कर ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बालावाला निवासी पुनीत अग्रवाल ने रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि वह परिवार के साथ बाहर गया था। आज जब वह वापस आया तो उसने देखा कि मकान का ताला टूटा हुआ था तथा अन्दर सारा सामान बिखरा हुआ था। चोर उसके यहां से सोने के जेवरात व 40 हजार रुपये नगद चोरी करके ले गये हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

अंतर्राज्यीय नकबजन गिरोह के तीन सदस्य गिरफ्तार

हमारे संवाददाता
देहरादून। बंद मकान में हुई लाखों की चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने अंतर्राज्यीय नकबजन गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। जिनके पास से चुरायी गयी कार, लाखों की ज्वैलरी व नगदी तथा तमंचा, कारतूस व धारदार हथियार बरामद किये गये हैं।



लाखों की ज्वैलरी, नगदी, कार व हथियार बरामद

मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी गयी। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस टीमों द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद बीती रात एक सूचना के आधार पर तेलपुर चौक से आगे टी-स्टेट के पास से

तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से चुरायी गयी कार, 1 लाख 5 हजार की नगदी, डेढ़ लाख की ज्वैलरी, तमंचा, कारतूस व दो धारदार हथियार बरामद किये गये हैं। पृष्ठताछ में उन्होंने अपना नाम मंगलू पुत्र प्रफुल्ल निवासी दिल्ली, मनोज पुत्र राजवीर निवासी दिल्ली व अजय पुत्र रामपाल निवासी गाजियाबाद बताया। बताया कि वह तीनों 6-7 दिसम्बर की रात को दिल्ली से देहरादून आये थे जिनके द्वारा उक्त चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। आज भी हम किसी अन्य वारदात को अंजाम देने देहरादून आये थे लेकिन पकड़े गये। पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।

दो लोग चाकू सहित दबोचे



हमारे संवाददाता
हरिद्वार। वारदात की फिराक में घूम रहे बदमाशों को पुलिस ने अलग-अलग क्षेत्रों से गिरफ्तार कर लिया है। जिनके पास से दो धारदार चाकू बरामद हुए हैं। जानकारी के अनुसार बीती रात कोतवाली सिडकुल पुलिस गश्त पर थी। इस दौरान पुलिस को अलग-अलग क्षेत्रों में दो संदिग्ध घूमते हुए दिखायी दिये। पुलिस ने जब उन्हें रोककर तलाशी ली तो उनके पास से दो धारदार चाकू बरामद हुए। पृष्ठताछ में उन्होंने अपना नाम विशाल पुत्र मुकेश, निवासी जगन वाला, हलदौर, जनपद बिजनौर, हाल पता प्रीत विहार कॉलोनी, ब्रह्मपुरी, थाना सिडकुल, जनपद हरिद्वार व पंकित पुत्र बाबूराम, निवासी रावली महदूद, थाना सिडकुल, जनपद हरिद्वार बताया। पुलिस ने उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।

वर्ष 2026 के लिए उत्तराखण्ड पुलिस का रोडमैप तय

हमारे संवाददाता
देहरादून। पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड दीपम सेठ द्वारा वर्ष 2026 के लिए निर्धारित उत्तराखण्ड पुलिस की प्राथमिकताओं के संबंध में सरदार पटेल भवन में पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ



दिए जाने के निर्देश दिए गए। एटीएस व एएनटीएफ एवं ट्रेफिक निदेशालय के पुनर्गठन पर विशेष जोर दिया गया। एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस-2025 में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा एटीएस की संरचना में एकरूपता पर दिए गए निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई तथा मुख्यमंत्री के डूंग-फ्री उत्तराखण्ड के विजन को साकार करने हेतु एएनटीएफ को इस वर्ष और अधिक सुदृढ़ किए जाने के निर्देश दिए गए।

शीघ्र ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें डीजीपी-आईजी

कांफ्रेंस-2025 के एजेंडा बिंदुओं की समीक्षा कर उनके प्रभावी क्रियान्वयन एवं भविष्य की पुलिस रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। साइबर अपराधों की त्वरित शिकायत निस्तारण हेतु 1930 हेल्पलाइन को और अधिक प्रभावी बनाते हुए 112 इमरजेंसी सिस्टम से उसके बेहतर एवं तकनीकी रूप से मजबूत समन्वय पर विशेष बल दिया गया। मुख्यालय स्तर पर सभी अधिकारी अपने-अपने अनुभागों से संबंधित प्रस्तावों, प्राथमिकताओं एवं लक्ष्यों के अनुरूप टोस एवं समयबद्ध एक्शन प्लान तत्काल प्रस्तुत करेंगे। साथ ही वित्तीय वर्ष की समाप्ति (31 मार्च) से पूर्व

बजट, प्रोक्रोरमेंट एवं अन्य वित्तीय मामलों का शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। विगत वर्ष की लंबित पत्रावलियों तथा शासन स्तर पर लंबित प्रस्तावों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए, जिससे प्रशासनिक कार्यों में अनावश्यक विलंब को रोका जा सके। बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था वी. मुरुगेशन, अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन ए. पी. अंशुमान, पुलिस महानिरीक्षक, दूरसंचार कृष्ण कुमार वी.के., पुलिस महानिरीक्षक, साइबर नीलेश आनन्द भरणे, पुलिस महानिरीक्षक/निदेशक यातायात एन.एस. नपलच्याल, पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण अनन्त शंकर ताकवाले, पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल परिक्षेत्र राजीव स्वरूप, पुलिस महानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था सुनील कुमार मीणा, धीरेन्द्र गुंज्याल, पुलिस उप महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी व पुलिस मुख्यालय के समस्त अनुभाग अधिकारी उपस्थित रहे।

डीजीपी दीपम सेठ की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक

अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस मुख्यालय की सभी शाखाओं की कार्यप्रणाली में दक्षता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदमों पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक के दौरान डीजीपी द्वारा महत्वपूर्ण निर्देश प्रदान किए गये। जिनमें एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस-2025 के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में, राज्य की आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से साइबर सर्विलांस एवं साइबर इंटेल्जेंस को विशेष प्राथमिकता

आर.एन.आई.- 59626/94
स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक श्रीमती पुष्पा कांति कुमार द्वारा दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग घंटाघर, देहरादून से प्रकाशित तथा अवि प्रिंटर्स 21 ईसी रोड, देहरादून से मुद्रित।

प्रधान संपादक
कांति कुमार

संपादक
पुष्पा कांति कुमार

समाचार संपादक
आनंद कांति कुमार

कानूनी सलाहकार:
वी के अरोड़ा, एडवोकेट
बैजनाथ, एडवोकेट

कार्यालय: दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग देहरादून।
मो. 9358134808

नोट: सभी विवादों के लिये देहरादून न्यायालय ही मान्य होगा, प्रकाशित सामग्रियों के लिए प्रिंटर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।